



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 123/19

निर्णय दिनांक: 30-08-2019

1. भगवानाराम पुत्र जगमालराम जाति बिश्नोई निवासी रासीसर पुरोहितमान का बास, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 16-02-1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:-

1. सुश्री रोशनआरा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 16-02-1984 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 2 सीडी के मुरब्बा नम्बर 97/27 के किला नम्बर 13, 18, 21 ता 23 व किला नम्बर 2 ता 5, 8 ता 12, 19, 20 में 16 बीघा व मुरब्बा नम्बर 97/36 के किला नम्बर 10 ता 13, 17 ता 25 में 09 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 16-02-1984 को किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के




अधीनस्थ अपील अधिकारी,
बीकानेर


उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट में प्रकाशित होकर अन्य को आवंटित होने तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट में अन्य को आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ ना ही समान श्रेणी की अन्य भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4.

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-02-1984 के विरुद्ध अपील दिनांक 22-07-2019 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर


अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील है। अपीलांट को दिनांक 16-02-1984 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-02-1984 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 22-07-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ग्रामीण परीवेश का अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति है। जिसे न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी होने पर अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



7. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 2 सीडी के मुरब्बा नम्बर 97/27 के किला नम्बर 13, 18, 21 ता 23 व किला नम्बर 2 ता 5, 8 ता 12, 19, 20 में 16 बीघा व मुरब्बा नम्बर 97/36 के किला नम्बर 10 ता 13, 17 ता 25 में 09 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट के तहत अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी।

प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नम्बर 2 के दौहरे आवंटन के प्रकरण में पटवारी हल्का छीला 'बी' द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अभिलिखित


व्यापारिक अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया है कि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा उपरोक्त भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन किया जाना विधि विरुद्ध आवंटन की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जाँच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित व अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है। आवंटन अधिकारी द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि का आवंटन किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

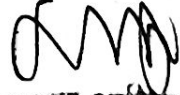


8.

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 16-02-1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9.

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30-08-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी
(सामान्य जटि)
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर